



समक्ष:- माननीय / सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

48

पुनर्विलोकन याचिका कमांक-
पुनर्विलोकन / सिवनी / भू-रा/2018/1243

प्रस्तुत दिनांक / / 2018

श्रीमंत सेठ गोपालसाव पूरनसाव
दिगम्बर जैन परमार्थिक ट्रस्ट सिवनी,

द्वारा सचिव श्री प्रमोद जैन,
तहसील सिवनी (म.प्र.)
- विरुद्ध -

आवेदक

मध्यप्रदेश शासन

द्वारा- कलेक्टर, कलेक्ट्रेट सिवनी,
तहसील व जिला सिवनी

अनावेदक

दि. 19/2/18
प्रारम्भिक तर्क
6/3/18 नियम।
कलक आर कोर्ट
स्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन याचिका अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता।

आवेदक निम्न विनय प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि, आवेदक ने जिला कलेक्टर सिवनी द्वारा विविध प्रकरण कमांक 68/बी-121/14-15 में पारित आदेश दिनांक 29.12.2016 से दुखी होकर माननीय महोदय के समक्ष निगरानी प्रकरण आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया था। जिस पर सम्माननीय महोदय द्वारा दिनांक 04.10.2017 को पारित आदेश के अनुसार आवेदक का निगरानी प्रकरण कमांक आर-758-1/2017 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर (डी.बी.) द्वारा रिट अपील कमांक 936/11 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2011 के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र होने के निर्देश देते हुए निरस्त करने के संबंध में यह पुनर्विलोकन याचिका निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

II प्रकरण के तथ्य संक्षेप में।।

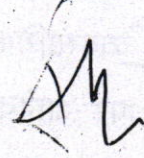
1- शहर सिवनी तहसील तथा जिला सिवनी में स्थित सिविल स्टेशन वार्ड ब्लॉक नं0 6, प्लॉट नंबर 10 क्षेत्रफल 411866 वर्गफुट नजूल प्लॉट का स्थायी पट्टेदार आवेदक ट्रस्ट है। उक्त नजूल प्लॉट में से 22658 वर्गफुट नजूल प्लॉट व्यवसायिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रयोजनार्थ दिनांक 31.03.2025 तक स्थायी पट्टे पर आवेदक ट्रस्ट को नियमानुसार प्रदान किया गया जिसका बटांक 10/2 किया गया और शेष नजूल प्लॉट रकबा 389208.83 वर्गफुट नजूल प्लॉट नंबर

जोद नागव
25/02/18
ग्वालियर
1-02-2018

न्यायालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
दिनांक 19/2/18

Premod Kumar 2

I/दिव्यु/सिवनी/१२१/२०१८/१२५३

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--|
| ०२-०८-१८ | <p>प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह पुनरावलोकन आवेदन न्यायालय के प्रकरण क्रमांक ७५८-एक/२०१७ निगरानी में पारित आदेश दिनांक ४-१०-२०१७ पर से म०प्र०भू राजस्व संहिता १९५९ की धारा ५१ के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है।</p> <p>२/ पुनरावलोकन आवेदन में अंकित आधारों के क्रम में आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर किया गया। प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि कलेक्टर जिला सिवनी के प्रकरण क्रमांक ६८ बी-२१/२०१४-१५ में पारित आदेश दिनांक २९-१२-२०१६ के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी क्रमांक ७५८-एक/२०१७ निगरानी आदेश दिनांक ४-१०-२०१७ से इस आधार पर अमान्य की गई है कि आवेदक ट्रस्ट को नजूल प्लॉक नंबर ६ प्लॉट नंबर १०/१, १०/२ कुल रकबा ३५३४ वर्गमीटर पर माननीय उच्च न्यायालय (डी०बी०) से रिट अपील क्रमांक ९३६/२०११ में पारित आदेश दिनांक १४-९-११ में विहित आदेश से हटकर अपर कलेक्टर सिवनी ने क्षेत्राधिकार के वाहर जाकर निर्माण की अनुज्ञा दी थी। कलेक्टर सिवनी के समक्ष पुनरावलोकन प्रकरण आने पर प्रकरण क्रमांक ६८ बी-२१/२०१४-१५ में पारित आदेश दिनांक २९-१२-२०१६ से अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया गया है जो माननीय उच्च न्यायालय के रिट अपील क्रमांक ९३६/२०११ में हुये आदेश दिनांक १४-९-११ के अनुरूप है एवं आदेश दिनांक ४-१०-२०१७ में अभिनिर्धारित है कि यदि आवेदक माननीय उच्च न्यायालय (डी०बी०) से रिट अपील क्रमांक ९३६/२०११ में पारित आदेश दिनांक १४-९-११ से दुखी है तब इस आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में जाने के लिये स्वतंत्र है। फलतः आदेश दिनांक ४-१०-२०१७ में किसी प्रकार की कम-वेशी नहीं है। म०प्र०भू राजस्व संहिता १९५९ की धारा ५१ में पुनरावलोकन के लिये निम्न आधार बताये गये हैं-</p> <p>१/ किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या,</p> <p>२/ मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती,</p> <p>३/ कोई अन्य पर्याप्त कारण।</p> <p>आवेदक के अभिभाषक ऐसा आधार प्रस्तुत कर समाधान नहीं करा सके हैं कि आदेश दिनांक ४-१०-२०१७ में उक्त में से कौनसी विसंगति है जिसके आधार पर पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जावे। पुनरावलोकन आवेदन आधारहीन होने से अमान्य किया जाता है।</p> |  सदस्य |